

तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

बनाम

आंध्र प्रदेश सरकार

(एके सरकार, केसी दास गुप्ता और एन. राजगोपाल अय्यंगार, जेजे)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) - आदेश 47, नियम 1-
समीक्षा - स्पष्ट त्रुटि - का अर्थ-समीक्षा छिपी हुई अपील नहीं है - एक
गलत निर्णय को प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

अभ्यास और प्रक्रिया- विशेष/अनुमति देने से पहले प्रतिवादी को
नोटिस- क्या विशेष अवकाश प्रदान करने के बाद अनुमति दी गई अपील
की विचारणीयता पर आपत्ति- सुप्रीम कोर्ट नियम, 1950, O. XIX, r. 4.

आकलन वर्ष 1949-50 के संबंध में, अपीलकर्ता ने तेल की बिक्री के अपने
कारोबार का खुलासा करते हुए अपनी रिटर्न जमा करते समय, उसमें
हाइड्रोजनीकृत तेल का मूल्य शामिल किया जिसे उसने बेचा था और आर
के तहत कटौती का दावा किया था। (ख) मूंगफली के मूल्य के संबंध में
कारोबार और आकलन नियमावली की धारा 1 8 जिसका उपयोग
हाइड्रोजनीकृत तेल में परिवर्तित करने के लिए किया गया था, जिस पर
उसने उनकी खरीद के समय कर का भुगतान किया था। बिक्री कर

अधिकारियों ने इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल उस नियम के तहत मूंगफली का तेल नहीं था। इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी, 1955 को बरकरार रखा था। अपीलकर्ता द्वारा दायर 1953 के कर पुनरीक्षण केस नंबर 120 में, लेकिन, आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया कि मामले में निर्णय के लिए कानून के पर्याप्त प्रश्न उठे। मूल्यांकन वर्ष 1950 के लिए.

(क) क्या 1951-52 और 1952-53 में यही प्रश्न था कि क्या बिक्री कर प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल उठाया गया था और निर्णय लिया गया था। इसके बाद अपीलकर्ता ने आवेदन किया। फिटनेस के प्रमाण पत्र के लिए। संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के अनुसार, लेकिन उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर, 1959 को याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था: "जिस फैसले के खिलाफ अपील करने की मांग की गई है, वह पुष्टि में से एक है। हमें नहीं लगता कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है

न ही हम इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्त मामला मानते हैं। 23 नवंबर, 1959 को, समीक्षा के लिए आवेदन 0 के तहत दायर किए गए थे। (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47, आर एल लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता ने तब पुनर्विचार के लिए आवेदनों को खारिज करने के आदेशों के खिलाफ संविधान के

अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश के लिए आवेदन किया और प्रतिवादी को नोटिस के बाद छुट्टी दे दी गई। जब अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आई, तो याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि अपीलकर्ता को दी गई विशेष छुट्टी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 136 के तहत आवेदनों की सुनवाई के समय प्रतिवादी द्वारा विशेष अवकाश को रद्द करने के आधार का आग्रह नहीं किया गया था, न ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट नियम, 1950 के ओ. XVIII के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर मामले के बयान में निर्धारित किया गया था।

अभिनिर्धारित : (i) जहां विशेष अवकाश प्रदान करने के आवेदन की सुनवाई से पहले प्रतिवादी को नोटिस दिया जाता है, वहां अपील की विचारणीयता या अनुदान देने पर कोई आपत्ति नहीं है। विशेष अवकाश प्रदान किए जाने के बाद किसी भी स्तर पर अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि संभवतः जहां अवकाश प्रदान किए जाने के बाद आग्रह किया गया आधार उत्पन्न होता है या जहां उचित देखभाल के बावजूद उस तारीख को प्रतिवादी द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ii) 4 सितंबर, 1959 के आदेश में दिया गया यह कथन कि इस मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, 0 के अर्थ में "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि" थी। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47,

आर.एल. चूंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें बिना किसी विस्तृत तर्क के कोई भी त्रुटि की ओर इशारा कर सकता था और कह सकता था कि यहां कानून का एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो सामने आ गया था।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: दीवानी अपीलें नं. 781-783 वर्ष 1962

विशेष अनुमति द्वारा अपील विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सिविल विविध याचिका सं. 4672-4674 वर्ष 1960 में आदेश व निर्णय 6 जनवरी, 1961

ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, एम. एस. के. शास्त्री और एम. एस. नरसिम्हन, अपीलार्थी के लिए (सभी अपीलों में)।

ए. रंगनाथम चेट्टी और आर. एन. सचथे, प्रत्यर्थी के लिए (सभी अपीलों में)।

22 अक्टूबर, 1963 न्यायालय का निर्णय

अय्यंगार, जे. द्वारा दिया गया था इन तीन अपीलों में उठाए गए बिंदु जो संविधान के आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति के आधार पर हमारे सामने आते हैं। कुछ हद तक सामान्य से हटकर हैं और इस बात पर विचार करने के लिए उठते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश उस अदालत द्वारा पहले के आदेश की समीक्षा करने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया है, उन तथ्यों पर सही है जो

हम वर्तमान में बताएंगे।

अपीलकर्ता - मेसर्स तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मूंगफली तेल के निर्माता हैं, जिसका एक हिस्सा वे हाइड्रोजनीकृत तेल में बिक्री के लिए छिपाते हैं जबकि बाकी को साधारण तेल के रूप में बेचा जाता है। मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम के तहत, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य पर लागू होता है, जबकि मूंगफली के संबंध में खरीद के बिंदु पर कर लगाया जाता है, मूंगफली के तेल पर बिक्री के बिंदु पर कर लगाया जाता है। इस सुविधा का परिणाम स्वाभाविक रूप से यह है कि जब कोई व्यक्ति मूंगफली खरीदता है और उसे तेल में परिवर्तित करता है और निकाले गए तेल को बेचता है तो उसे दोनों बिंदुओं पर कर का भुगतान करना पड़ता है। इस दोहरे शुल्क के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं। टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों का नियम 5(के) प्रदान करता है:

"5. (के) मूंगफली तेल और केक के एक पंजीकृत निर्माता के मामले में, वह राशि जिसे वह नियम 18 के तहत अपने सकल कारोबार से उस नियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कटौती करने का हकदार है"।

और नियम 18 में कहा गया है:

"18. (1) कोई भी डीलर जो मूंगफली और/या उसके द्वारा खरीदी गई गिरी से मूंगफली का तेल और केक बनाता है, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र

रखने वाले मूल्यांकन प्राधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें वह अपना व्यवसाय करता है, मूंगफली का तेल और केक निर्माता के रूप में पंजीकृत हो सकता है।

(2) मूंगफली तेल का ऐसा प्रत्येक पंजीकृत निर्माता नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (के) के तहत उसके द्वारा खरीदी गई और तेल व केक में परिवर्तित मूंगफली और/या गिरी के मूल्य के बराबर कटौती का हकदार होगा। यदि उसने ऐसी खरीद पर राज्य को कर का भुगतान किया है:

बशर्ते कि वह राशि जिसके लिए तेल बेचा गया है, उसके शुद्ध कारोबार में शामिल है:

आगे बशर्ते कि टर्नओवर की राशि जिसके संबंध में कटौती की अनुमति है, तेल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मूंगफली और/या गिरी के कारण होने वाले टर्नओवर की राशि से अधिक नहीं होगी और शुद्ध टर्नओवर में शामिल है।

अपीलकर्ता निश्चित रूप से एक निर्माता है जो उस नियम के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत है।

वर्ष 1949-50 के संबंध में अपीलकर्ता ने तेल की बिक्री के अपने टर्नओवर का खुलासा करते हुए अपना रिटर्न जमा करते समय, उसमें बेचे गए हाइड्रोजनीकृत तेल का मूल्य शामिल किया और मूल्य के संबंध में

नियम के तहत कटौती का दावा किया। मूंगफली का उपयोग हाइड्रोजनीकृत तेल में रूपांतरण के लिए किया गया था, जिस पर उन्होंने खरीद के समय कर का भुगतान किया था। इस दावे को बिक्री कर अधिकारियों ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियम 18(2) के तहत "हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल" "मूंगफली तेल" नहीं था। कटौती के अपने दावे को अनुमति दिलाने में विभागीय अधिकारियों के समक्ष असफल होने के बाद, अपीलकर्ता ने अपनी फाइल पर 1953 के कर संशोधन मामले संख्या 120 के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 1955 के अपने फैसले द्वारा, विभाग के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। इसके बाद आर्टिकल 133(1) के तहत फिटनेस का प्रमाण पत्र देने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया गया था। इस आधार पर कि सामान्य बिक्री कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की व्याख्या के साथ-साथ अपीलकर्ताओं द्वारा उनके दावे के समर्थन में भरोसा किए गए कुछ अन्य अधिनियमों के बारे में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठे। विद्वान न्यायाधीशों ने 21 फरवरी, 1956 के अपने आदेश द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अपील में उठने वाले बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि इस आदेश का पाठ निर्धारित करना सुविधाजनक होगा:

"यह याचिका सामान्य महत्व का सवाल उठाती है कि क्या हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल, जिसे लोकप्रिय रूप से वनस्पति के नाम से जाना जाता है, मूंगफली का तेल है, ताकि निर्धारिती को मद्रास जनरल

सेल्स टैक्स अधिनियम, 1939 की धारा 3 और उप नियम 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा तैयार किए गए टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों के नियम 18 (2) और 5 (1) (जी) के तहत छूट का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस मामले में उठने वाले प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद मूंगफली के तेल की मुख्य विशेषताएं वही रहती हैं। इसमें आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम और वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश के कुछ प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की व्याख्या भी शामिल है। इन परिस्थितियों में हम इसे एक मानते हैं उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला है, इसलिए अनुमति दी जाती है।"

इसके बाद इस न्यायालय में अपील पर विचार किया गया और इसे 1958 की सिविल अपील 498 के रूप में क्रमांकित किया गया, अंततः 18 अक्टूबर, 1960 को इसका निस्तारण कर दिया गया और अब इसे मैसर्स तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम का वाणिज्यिक कर अधिकारी , कुरनूल के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

इस बीच, तीन आगामी वर्षों - 1950-51, 1951-52 और 1952-53 के मूल्यांकन के संबंध में, वही प्रश्न कि क्या "हाइड्रोजनीकृत मूंगफली तेल" जो "मूंगफली तेल" था, टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों के नियम 18(2)

के तहत खरीद कारोबार की कटौती का हकदार था और बिक्री कर अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ निर्णय लिया गया। यह आदेश अपीलकर्ता द्वारा वाणिज्यिक कर के उपायुक्त के समक्ष अपील में लिया गया था और जैसा कि स्पष्ट रूप से समान प्रश्न वर्ष 1949-50 के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित था, अपीलीय प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की और जब 11 फरवरी, 1955 को अपीलकर्ता के खिलाफ टीआरसी 120/1953 का निर्णय लिया गया, 5 अप्रैल, 1955 के अपने आदेश द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ अपील का निपटारा किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक औपचारिकता थी क्योंकि न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के फैसले से बाध्य थे और 20 अक्टूबर, 1955 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी गई। बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलकर्ता ने 1956 के तीन मूल्यांकन वर्ष के तीन कर संशोधन मामलों - टीआरसी 75, 76 और 77 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने वर्ष 1949-50 के मूल्यांकन के संबंध में 1953 के टीआरसी 120 में अपने पहले निर्णय के बाद 7 अक्टूबर 1958 को तीन पुनरीक्षण मामलों को खारिज कर दिया। इस तिथि पर, यह देखा जाएगा कि 1953 के टीआरसी 120 में उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता आर्टिकल 133(1) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर इस न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित थी। इन

तीन कर संशोधन मामलों में भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर करने की इच्छा रखते हुए, अपीलकर्ता ने 16 फरवरी, 1959 को संविधान के आर्टिकल के 133(1) के तहत तीन विविध याचिकाएं दायर कर उपयुक्तता के प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना की गई है कि मामले में बिक्री कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों आदि की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीशों ने 4 सितंबर के अपने आदेश द्वारा, 1959 ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी:

"जिस फैसले के खिलाफ अपील करने की मांग की गई है वह पुष्टि में से एक है। हमें नहीं लगता कि इसमें संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है; न ही हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त मामला मानते हैं।"

इन अपीलों में विचार के लिए मुख्य रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या 4 सितंबर, 1959 का यह आदेश रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित है। वह मामला इसलिए प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अपीलकर्ता ने राहत के लिए O XLVII r 1 सीपीसी के तहत इस आदेश की समीक्षा के लिए तीन आवेदन दायर किए। समीक्षा के लिए ये आवेदन 23 नवंबर, 1959 को दायर किए गए थे, और जाहिर तौर पर प्रतिवादी-राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया था और समीक्षा के लिए याचिका 6 जनवरी, 1961 को

सुनवाई के लिए आई थी। उस तारीख को विद्वान न्यायाधीशों ने उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया और नियुक्त किया गया उनके आदेश के निम्नलिखित कारण हैं:

"इन समीक्षा याचिकाओं के समर्थन में तर्क दिया गया एकमात्र आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति पिछले वर्ष की समान परिस्थितियों में दी गई थी और ऐसा कोई कारण नहीं था कि इन मामलों में अनुमति देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए था। हम ऐसा नहीं सोचते हैं यह सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति के लिए याचिकाओं को खारिज करने के आदेश की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करेगा। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्थानांतरित किया गया था और जिसे खारिज कर दिया गया था, वह इस आधार पर हो सकता है कि इसे समय पर दाखिल नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि 1959 के एससीसीएम पीएस नंबर 4823, 4825 और 4827 को खारिज करने वाले हमारे दिनांक 4.9.1959 के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती है।"

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने इस अंतिम आदेश की सत्यता को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय से विशेष अनुमति के लिए आवेदन

किया और प्रतिवादी को नोटिस के बाद अनुमति दी गई, अपील अब हमारे सामने है।

अपीलकर्ता की ओर से हमें संबोधित तर्कों से निपटने से पहले, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता को दी गई विशेष अनुमति रद्द कर दी जानी चाहिए। हमने मुख्य रूप से दो कारणों से इस मामले में प्रतिवादी को इस तरह के किसी भी तर्क की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सबसे पहले, विशेष अनुमति प्रतिवादी को नोटिस के बाद दी गई थी और इसलिए अपील की स्थिरता या विशेष अनुमति देने पर किसी भी आपत्ति के बारे में प्रतिवादी को सुनने के बाद दी गई थी। इन परिस्थितियों में, इन मामलों के संबंध में किसी भी आधार का आग्रह उसी स्तर पर किया जाना चाहिए था और संभवतः कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर, जहां आग्रह किया गया आधार विशेष अनुमति के अनुदान के बाद उत्पन्न होता है या जहां यह प्रतिवादी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका है उस तिथि पर उचित देखभाल के बावजूद नहीं; ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, यह न्यायालय प्रतिवादी को विशेष अनुमति देने वाले न्यायालय के आदेश की सत्यता के संबंध में किसी भी तर्क का आग्रह करने की अनुमति नहीं देगा। वास्तव में, अनुमति देने से पहले प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाद वाले को अदालत के ध्यान में उन आधारों को लाने का अवसर दिया जाए जिनके आधार पर अनुमति से

इनकार किया जाना चाहिए और नियम का उद्देश्य होगा। यदि प्रतिवादी को बाद के चरण में - अपील की सुनवाई के चरण में और अपीलकर्ता द्वारा सभी लागतें वहन करने के लंबे समय बाद - यह आग्रह करने की अनुमति दी गई कि उसे नोटिस के बाद दी गई अनुमति को उपलब्ध आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए, तो निराशा होगी जब विशेष अनुमति के लिए अपील सुनी गई। इसके अलावा, प्रतिवादी की ओर से दायर मामले का बयान भी ऐसे किसी आधार का खुलासा नहीं करता है जिस पर दी गई अनुमति रद्द की जानी चाहिए; न ही, निःसंदेह, यह ऐसी राहत पाने के लिए कोई प्रार्थना करता है। मामले का विवरण जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है उनमें से एक स्पष्ट रूप से यह है कि सुनवाई में किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के नियमों में से O XIX r 4 में यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया है:

"कोई भी पक्ष, न्यायालय की अनुमति के बिना, उसके द्वारा दायर मामले के बयान में निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी भी आधार पर सुनवाई पर भरोसा नहीं करेगा।"

न ही, निश्चित रूप से, कोई विवाद था कि जिस आधार को प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था वह मामले का बयान दर्ज होने के बाद अस्तित्व में आया था। यह इन परिस्थितियों में था कि हमने प्रतिवादी को एक तर्क विकसित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया ताकि हम

यह मान सकें कि इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति को रद्द कर दिया जाना चाहिए, हालांकि हम यह जोड़ सकते हैं कि इस संबंध में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उल्लिखित मामला होगा। विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान आग्रह किए जाने पर भी, विशेष अनुमति के अनुदान का विरोध करने में उसे कोई भौतिक सहायता नहीं मिली। वह जिस मुद्दे पर आग्रह करना चाहते थे वह यह था कि विशेष अनुमति के लिए याचिका में अपीलकर्ता ने कहा था कि 1953 के टीआरसी 120 में उच्च न्यायालय के फैसले को उलटने वाले इस न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, लेकिन यह कथन दो कारणों से गलत या असत्य होना चाहिए: (1) अपील के तहत अब आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, और (2) इस न्यायालय के निर्णय को किसी भी कानून रिपोर्ट-आधिकारिक या अनौपचारिक -में लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं किया गया था। जनवरी 1961 के बाद जब समीक्षा याचिका पर सुनवाई हुई। यह स्पष्ट है कि दोनों में से कोई भी परिस्थिति स्वयं विशेष अनुमति याचिका में दिए गए कथन की असत्यता को साबित नहीं करेगी। विद्वान न्यायाधीशों ने अच्छी तरह से सोचा होगा कि निर्णय का उस एकमात्र बिंदु पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है जो उनके समक्ष विचार के लिए आया था, अर्थात्, सितंबर 1959 का उनका आदेश उस प्रकार की त्रुटि से दूषित था या नहीं जो ओ XLVII आर 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के भीतर लाया था। इस तरह देखा जाए तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। जहां तक दूसरे बिंदु

का संबंध है, अपीलकर्ता को कानून रिपोर्ट में मामले की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने इस न्यायालय के फैसले की एक प्रति पेश की होगी - और यहां कार्यवाही में एक पक्ष होने के नाते यह असंभव है कि इसकी कोई प्रति नहीं थी, इसलिए, इसका यह कथन कि इसने न्यायालय का ध्यान निर्णय की ओर आकर्षित किया, जनवरी, 1961 के काफी समय बाद तक निर्णय की सूचना न दिए जाने से झूठा साबित नहीं होता है। इसलिए दी गई अनुमति को रद्द करने के लिए मौखिक आवेदन को पूरी तरह से पदार्थहीन मानकर बाहर निकाल दिया जाता है।

हम आगे अपीलों के गुणावगुण पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालाँकि, ऐसा करने से पहले उस परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है जिसे विद्वान न्यायाधीशों ने समीक्षा याचिका खारिज करने का उचित कारण माना। यह 6 जनवरी, 1961 के अपने आदेश में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा समीक्षा देने से इनकार करने के लिए दिए गए दूसरे आधार से उत्पन्न हुआ है। इसे उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया जा सकता है:

"इसके अलावा, संविधान की धारा 136 के तहत विशेष अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था, शायद इस आधार पर कि इसे समय पर दायर नहीं किया गया था।"

इस मामले के संबंध में तथ्य अब बताए जा सकते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करने वाले 4 सितंबर, 1959 के आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन 23 नवंबर, 1959 को दायर किए गए थे। उन समीक्षा आवेदनों के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने 30 नवंबर, 1959 को इस पर विशेष अनुमति की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिकाएं दायर कीं लेकिन वे याचिकाएँ नियमों द्वारा निर्धारित सीमा अवधि से परे दायर की गईं। इसलिए विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें याचिकाएं दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की मांग की गई थी। विलंब माफ़ी के लिए याचिकाएँ और आवेदन एक साथ सुनवाई के लिए आए और इस न्यायालय ने देरी माफ़ करने से इनकार कर दिया, जिससे विशेष अनुमति की याचिकाएँ कानूनी तौर पर इस न्यायालय की फ़ाइल पर कभी नहीं आईं।

आदेश XLVII नियम 1(1) सीपीसी समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर करने की अनुमति देता है "एक डिक्री या आदेश से जिसके खिलाफ अपील की अनुमति है लेकिन जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है।" वर्तमान मामले में, यह देखा जाएगा, जिस तारीख पर समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया गया था, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में अपील दायर नहीं की थी और इसलिए O XLVII r1(1) की शर्तें समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए लागू नहीं होती। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस

स्थिति का विरोध नहीं किया। न ही हम उच्च न्यायालय के फैसले को उस आधार पर समीक्षा याचिका खारिज करने के रूप में पढ़ सकते हैं। O XLVII आर 1(1) की शर्तें निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि वह तारीख है जब समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया गया है। यदि उस तिथि पर कोई अपील दायर नहीं की गई है, तो समीक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय के पास अपील के लंबित होने के बावजूद गुण-दोष के आधार पर आवेदन का निपटान करने का अधिकार है, केवल इस शर्त के अधीन कि यदि समीक्षा के लिए आवेदन पर पहले अंतिम निर्णय लिया जाता है। अपील का निपटारा हो चुका है, समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा।

अगला प्रश्न विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने में देरी को माफ करने से इस अदालत के इनकार के प्रभाव के संबंध में है। यहां फिर से, यह तर्क नहीं दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा अभी बताए गए आधारों पर विशेष अनुमति के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार करना समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या शक्तियों पर रोक है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस स्थिति का विरोध नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने में देरी को माफ करने से इंकार करना एक ऐसी परिस्थिति थी जो या तो निर्णय लेने के लिए उच्च

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोक सकती थी या यहां तक कि इसे तय करने में ध्यान में रखा जाने वाला एक प्रासंगिक मामला भी हो सकता है। इसलिए, यदि 4 सितंबर 1959 का उनका मूल आदेश, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि के कारण दूषित हो गया था, तो जिन परिस्थितियों में यह घटित हुआ, इस न्यायालय में एसएलपी पर विचार न किया जाना, इन दोनों में से किसी का भी आधार नहीं हो सकता है। समीक्षा के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वयं या दूसरों के साथ लिया गया।

हम मानते हैं कि मुख्य प्रश्न की जांच करने के बाद अब अपील के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के पहले भाग पर विचार करना सुविधाजनक होगा कि क्या सितंबर, 1959 का आदेश, एक प्रमाण पत्र के लिए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करना, स्पष्ट त्रुटि से दूषित अभिलेख है। यदि किसी ने उस आदेश का विश्लेषण किया तो फिटनेस प्रमाणपत्र को अस्वीकार करने का केवल एक ही कारण बताया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने आदेश के पहले वाक्य में उन्होंने कहा कि निर्णय पुष्टि में से एक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह केवल प्रारंभिक था जहां उन्होंने दर्ज किया कि प्रमाण पत्र को इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि मामले में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था। हालाँकि, प्रारंभिक बयान कि उनका निर्णय पुष्टि में से एक था, यह दर्शाता है कि विद्वान न्यायाधीशों के मन में जहां अकेले संविधान का आर्टिकल 133 की शर्तें थीं - आर्टिकल 132 से अलग है

- प्रतिज्ञान के निर्णय का संदर्भ है, हालांकि प्रति इन्क्वैरियम में उन्होंने आर्टिकल 132(1) की शर्तों को पुनः प्रस्तुत किया। चूंकि यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं था कि इसमें संविधान की व्याख्या का कोई भी प्रश्न शामिल था, इसलिए "संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" का संदर्भ स्पष्ट रूप से उत्पन्न होने वाले कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए एक गलती रही होगी। हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सितंबर, 1959 के आदेश में इस आधार पर जोर दिया था, क्योंकि यह स्वयं रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि का खुलासा कर रहा था या कम से कम यह संकेत दे रहा था कि विद्वान न्यायाधीशों ने उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर विचार करने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाया। फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि यह उनके आदेश में केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी और विद्वान न्यायाधीशों ने वास्तव में आर्टिकल 133(1) की शर्तों का पालन किया था जिसे अपीलकर्ताओं ने प्रमाण पत्र के लिए अपने आवेदन में लागू किया था। इस आधार पर कि सितंबर, 1959 के आदेश में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जिक्र करने वाले शब्दों का वास्तव में यह कहना था कि इस न्यायालय में दायर की जाने वाली अपील में कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था। बात कैसे बनती है? व्यावहारिक रूप से उस तथ्य का कोई सवाल ही नहीं था जिस पर टीआरसी में निर्णय लिया जाना था। 1956 के 75 से 77 और एकमात्र प्रश्न

मूंगफली के मूल्य में कटौती के दावे से संबंधित है जिस पर खरीद कर का भुगतान किया गया था और जिसे हाइड्रोजनीकृत तेल में परिवर्तित किया गया था जिसे बेचा गया था और जिसे अपीलकर्ता के कारोबार में शामिल किया गया था। दरअसल, ये टी.आर.सी. उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से उनमें उभरे किसी विशेष तथ्य पर विचार करने के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि 1953 के टीआरसी 120 में उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए, जिसने उस निर्माण को स्वीकार कर लिया था जिसे विभागीय अधिकारियों ने टर्नओवर एवं मूल्यांकन नियमों की धारा 18(2) पर रखा था। अपील में कानून के जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के उत्पन्न होने का दावा किया गया था, उन्हें प्रमाण पत्र मांगने वाली याचिका में विस्तार से बताया गया था और वास्तव में, वे व्यावहारिक रूप से 1953 के टीआरसी 120 में फैसले के खिलाफ प्रमाण पत्र की मांग करने वाली पिछली याचिका की सामग्री का पुनरुत्पादन थे। विद्वान न्यायाधीशों - और विद्वान सीजे ने पहले के निर्णय और उस अवसर पर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने में एक पक्षकार थे - ने इन बिंदुओं पर विचार किया था और अपनी राय के रूप में कहा था कि मामले में सामान्य महत्व के कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल थे और उन्होंने एक फैसले में इन विचारों को अभिव्यक्ति दी थी जिसे हमने पहले पुनः प्रस्तुत किया है।

हालाँकि, अब हम इस बात से चिंतित हैं कि क्या सितंबर 1959 के आदेश में यह कथन कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल

नहीं है, "रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि" है। तथ्य यह है कि पहले के अवसर पर अदालत ने तथ्यों की एक समान स्थिति पर यह माना था कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ था, यह निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि पहले का आदेश स्वयं गलत हो सकता है। इसी तरह, भले ही बयान गलत हो, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह "रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि" थी, क्योंकि एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह केवल एक मात्र के बीच हमेशा प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। त्रुटिपूर्ण निर्णय और ऐसा निर्णय जिसे "स्पष्ट त्रुटि" से दूषित माना जा सकता है। समीक्षा किसी भी तरह से छिपी हुई अपील नहीं है जिसके तहत एक गलत निर्णय पर विचार किया जाता है और उसे ठीक किया जाता है, बल्कि यह केवल पेटेंट त्रुटि के लिए होता है। हम यह नहीं मानते हैं कि यह इस अंतर को विस्तृत रूप से या किसी बड़े विवरण से निपटने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, लेकिन हमारे लिए यह कहना पर्याप्त होगा कि जहां बिना किसी विस्तृत तर्क के कोई त्रुटि की ओर इशारा कर सकता है और कह सकता है कि यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है कानून जो किसी को भी घूरता है, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि का एक स्पष्ट मामला बनाया जाएगा। 1956 के 75 से 77 टीआरसी में उच्च न्यायालय के निर्णय में तथ्य का कोई प्रश्न शामिल नहीं था। सारा विवाद टर्नओवर और मूल्यांकन नियम 18(1) और कानून के अन्य टुकड़े जिन्हें उच्च न्यायालय ने फरवरी 1956 के अपने आदेश में संदर्भित किया

है की उचित व्याख्या पर केंद्रित हो गया; न ही इसमें संदेह या विवाद किया जा सकता है कि ये कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसलिए इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की दलील है कि सितंबर 1959 का आदेश O. XLVII r 1 सीपीसी द्वारा परिकल्पित प्रकार की "स्पष्ट त्रुटि" से दूषित हो गया था, जब कहा कि "कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा" तो हमें स्पष्ट रूप से उचित प्रतीत होता है। वास्तव में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश नहीं की कि सितंबर 1959 का पिछला आदेश ऐसी त्रुटि के कारण दूषित नहीं हुआ था।

हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या पहले का आदेश इतना दूषित था या नहीं बल्कि उन आधारों पर ध्यान देना चाहिए जो समीक्षा के लिए आवेदन की सुनवाई में अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए गए थे और यदि उस स्तर पर बिंदु जिस रूप में हमने अभी व्यक्त किया है, उसमें आग्रह नहीं किया गया था, यह न्यायालय समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा के लिए आवेदन पर बहस के चरण में न्यायालय के समक्ष एकमात्र आधार का आग्रह किया गया था, जैसा कि न्यायालय के फैसले से पता चलता है, कि सितंबर, 1959 का आदेश इस कारण से गलत था कि एक प्रमाण पत्र पिछले अवसर पर प्रदान किया गया था। हमने जनवरी, 1961 के इस आदेश का पाठ निकाला है जिसमें इस तर्क पर ध्यान दिया गया है और कहा गया है कि यह

न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया एकमात्र बिंदु था। फिर सवाल उठता है कि "पिछले वर्ष के संबंध में समान परिस्थितियों में" का क्या मतलब है। प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना है कि हमें इन शब्दों का अर्थ यह समझना चाहिए कि अपीलकर्ता ने 21 फरवरी 1956 के आदेश पर भरोसा किया था, जिसमें 1953 के टीआरसी 120 में उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया था। उस आधार पर विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि केवल यह तथ्य कि पहले वर्ष के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, पेटेंट त्रुटि के आधार पर बाद के वर्ष में प्रमाणपत्र देने से इनकार करने वाले आदेश को गलत नहीं ठहराएगा। हम मामले के इस पहलू से पहले ही निपट चुके हैं। हालाँकि, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह उस तर्क का उचित निर्माण है जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पिछले वर्ष के संबंध में दिनांक 21 फरवरी, 1956 का आदेश अदालत के समक्ष रखा गया था और इसे पालन करने के लिए एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं बल्कि अपील में निर्णय के लिए उठने वाले कानून के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्धारित करने के रूप में माना गया था, और न्यायालय का ध्यान पिछले आदेश की शर्तों की ओर आकर्षित किया गया था ताकि इन प्रश्नों के अस्तित्व की सराहना करने में विफलता को इंगित किया जा सके और सितंबर, 1959 के आदेश में कहा गया कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। अपीलों में शामिल होना प्रथमदृष्टया गलत था। यह समीक्षा के लिए याचिका की

सामग्री से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है जहां उस पहलू को स्पष्ट किया गया है जिसे हमने अभी निर्धारित किया है। पिछला आदेश एक ही न्यायालय और एक ही न्यायाधीशों से बनी एक पीठ का था, पहले के आदेश को कानून के विभिन्न बिंदुओं के सुविधाजनक सारांश के रूप में संदर्भित किया गया था जो न्यायालय के ध्यान में लाने के उद्देश्य से उत्पन्न हुए थे। उसने यह कहते हुए गलती की कि अपीलों में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा। यदि पहले वाक्य से विद्वान न्यायाधीशों का तात्पर्य यह था कि जिस विवाद पर उन्हें विचार करने के लिए बुलाया गया था, वह 1956 के पिछले आदेश को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में दावा करने के लिए निर्देशित किया गया था, तो वे अपीलकर्ता के तर्क के सार की सराहना करने में विफल रहे। जो कुछ भी हो, उनका मतलब था कि 1953 के टीआरसी 120 में उनके निर्णय के संबंध में प्रमाण पत्र देने के आदेश में उनके द्वारा निर्धारित मामले भी टीआरसी 75 से 77 तक उनके फैसले में शामिल नहीं थे, वे गलती में थे, क्योंकि यह किसी का भी मामला नहीं है कि इसमें शामिल कानून के प्रश्न समान नहीं थे। यदि, इसके अलावा, उनका कहने का मतलब यह था कि ये आर्टिकल 133(1)के भीतर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं थे, वे फिर से त्रुटि के दोषी थे। इसलिए, अब अपील के तहत आदेश में विद्वान न्यायाधीशों का तर्क, सितंबर, 1959 के उनके आदेशों की समीक्षा के लिए आवेदनों को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि विद्वान

न्यायाधीशों ने समीक्षा के लिए आवेदन को खारिज करने में गलती की थी और हम उनका मानना है कि समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए थी। हम केवल यह जोड़ना चाहते हैं कि ऐसा करते समय हमने इस न्यायालय द्वारा तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम व्हा वाणिज्यिक कर अधिकारी, कुरनूल, में टर्नओवर और मूल्यांकन नियमों के नियम 18(2) के निर्माण के संबंध में, व्यक्त किए गए विचार पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया है या उससे प्रभावित नहीं हुए हैं। क्योंकि यह निर्णय समीक्षा के लिए आवेदनों को खारिज करने वाले आदेश की शुद्धता पर विचार करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है, जो इन अपीलों में निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न है। निष्कर्ष निकालने से पहले हम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा हमसे की गई अपील से उत्पन्न एक टिप्पणी करना चाहते हैं कि भले ही अपील की अनुमति दी गई हो, हमें उसके ग्राहक के खिलाफ लागत के संबंध में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए। अपीलकर्ता का उस छूट का लाभ पाने का अधिकार जिसका उसने दावा किया था और जिसे टीआरसी 75, 76 और 77 में उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था, वास्तव में टर्नओवर और मूल्यांकन नियम 18(2) के सही निर्माण पर निर्भर थे और विशेष रूप से वहां होने वाली अभिव्यक्ति "मूंगफली तेल" के अर्थ पर-चाहे इसमें "हाइड्रोजनीकृत तेल" शामिल हो। इस न्यायालय ने अपने निर्णय में तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कुरनूल, में टर्नओवर और मूल्यांकन नियम 18 में आने वाले

'मूंगफली का तेल' शब्द के उचित निर्माण पर उच्चारण किया गया, जैसा कि वे तब थे। 1950-51, 1951-52 और 1952-53 की मूल्यांकन कार्यवाही सभी कार्यवाहियों की समाप्ति से निर्धारिती के विरुद्ध अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के लिए आवेदन अभी भी लंबित थे। इन परिस्थितियों में, यह अपेक्षा करना उचित होगा कि बिक्री कर अधिकारियों को अपीलकर्ता को इन बाद के वर्षों के संबंध में भी इस न्यायालय के निर्णय का लाभ देना चाहिए था, जब तक कि उनके रास्ते में कोई कठिन कठिनाई या अन्य परिस्थिति न हो। ऐसा करने पर, और प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं लायी है। यह अब तक कर संशोधन मामलों में विवाद के गुण-दोष के संबंध में है जिसमें प्रमाणपत्र मांगे गए थे। निःसंदेह, यदि किसी तकनीकी या समान बिंदु पर राज्य निर्विवाद रूप से सफल होने का हकदार है तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा और वे उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन और उसके पक्ष में निर्णय के अनुसार कर एकत्र करने के हकदार होंगे। लेकिन जब प्रतिवादी मामले को इस न्यायालय में आने से रोकने के लिए उठाई गई आपत्तियों में विफल रहता है, तो हमें इस दलील का कोई औचित्य नहीं दिखता कि लागत घटना के बाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपीलकर्ता को लागत के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए।

परिणाम में अपील की अनुमति दी जाती है और तीन अपीलों में उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय को उलट दिया जाता है और समीक्षा

के लिए याचिकाएं - सीएम पीएस 4672, 4673 और 1959 की 4674 उच्च न्यायालय की फाइल पर लागत के साथ यहां और उच्च न्यायालय में अनुमति दी जाती है - सुनवाई शुल्क का एक सेट।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रामचरण मीना (आर.जे.एस.) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान, द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।